Telangana Today- 17- November-2022

Polavaram backwaters will affect villages: TS

AP accused of failing to demarcate areas facing stagnation

STATE BUREAU
Hyderabad

Telangana State has stated that the backwater levels of Polavaram project impacting the Bhadrachalam town and surrounding villages would become a common phenomenon once the project was completed and water was stored at the Full Reservoir Level (FRL).

Telangana engineer-in-chief (irrigation) C Muralidhar, who attended the Polavaram Project Authority (PPA) meeting here on Wednesday, told the authorities that due to the backwater effect, there would also be a problem of local drainage congestion along the river banks and local streams such as Peddavagu, Edullavagu, Pamuleru vagu, Turubakavagu and 31 other major & medium streams causing loss and destruction in the areas in Telangana on either side of river Godavari.

He pointed out that the backwaters of the project were responsible for the inundation of Bhadrachalam town and surrounding villages after heavy rains lashed the State in July this year. The July floods have inundated 103 villages submerging a total area of 40,446 acres, he informed. According to him, the only possible solution for drainage of the low-lying area of Bhadrachalam town and the adjoining Burgampahad and Sarapaka would be continuous pumping.

He further stated that out of eight outfall regulators, 3 regulators for drainage at Vista complex, Kotha colony and Etapaka with sill levels below the FRL of Polavaram project will be under submergence throughout . These outfall regulators at Bhadrachalam town are to be kept closed during storage of Polavaram project and it is necessary to continuously lift the drainage and rain water accumulated at Outfall regulators to avoid inundation of Bhadrachalam town especially at Temple, he explained.

He stated that the Andhra Pradesh government had failed to demarcate the areas affected due to stagnation along Kinnersani and Murreduvagu which shall be undertaken on priority along with demarcation of the area affected due to similar issue in respect of 35 other streams.

He alleged that the AP government was taking up unauthorised Lift Irrigation Project on dead storage of Polavaram project. He further stated that though the AP government was directed to stop all activities and follow the stipulated procedure and submit the Detailed Project Report (DPR) of the scheme for appraisal to Godavari River Management Board(GRMB) and Central Water Commission(CWC) and approval of Apex Council, it was not following the norms.

Millennium Post- 17- November-2022

BJP targets Delhi govt over cleaning of Yamuna river

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The BJP on Wednesday accused Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal of "doing nothing" to clean the Yamuna river or control air pollution in the city despite making promises elections after elections.

BJP spokesperson Gaurav Bhatia claimed that the chief minister failed to clean the Yamuna despite governing the national capital for the last eight years, adding that the Centre and the Delhi L-G managed to clean a 3-km stretch of the river in just three-and-a-half months.

"Kejriwal had visited South Korea's Seoul in December 2018 to learn how a polluted river was cleaned there. What did he learn there that despite 50 months, Yamuna's all important parameters, including biochemical oxygen demand, dissolved oxygen and fecal coliform, are much above the permissible limit?" he asked.

The Yamuna has permissible limit of fecal coliform bacteria when it enters the city which rises to over 6.5 lakh/100 ml as the river leaves the city, he said.

"This over 1,200 per cent more fecal coliform bacteria than the permissible limit of 2,500 per 100 ml endangers the health of people in Delhi and also shows the inaction of the Kejriwal government," Bhatia said.

He further said that 126 drains pour into the Yamuna's 57 km stretch and so far only 32 of these have been intercepted, adding that as against the need of 20 sewage treatment plants (STPs), there are only five functioning plants, he said.

Delhi BJP president Adesh Gupta also targeted the AAP dispensation for "failing" to ensure the treatment of sewage flowing into the Yamuna.

"Way back in 2015, Kejriwal had promised during elections that the Yamuna would be cleaned if the AAP formed the government in Delhi, but it is still heavily polluted due to the inaction of his government," he charged.

West Delhi BJP MP Parvesh Verma said Kejriwal should visit Sabarmati riverfront in Gujarat to study how to clean the Yamuna.

Rashtriya Sahara- 17- November-2022

बुंदेलखंड में धुलेंगे पानी के दाग

जल प्रबंधन

डॉ. शिप्रा माथुर

दुनिया की दो तिहाई आबादी पानी की कमी की चपेट में है। संकट लगातार गहरा रहा है और भारत ने भी विकास की अपनी रफ्तार में जमीन का इतना पानी खींच लिया है कि इस बार मानसून मेहरबान होने के बावजूद भूगर्भ में पानी का ठहराव नहीं हो पाएगा। जितना बरसा उससे ज्यादा खींच लेने की रस्साकशी में जमीन ने आसमान को मात दे दी है। जो संकट कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान के सूखे इलाकों में है, उतना ही उत्तर प्रदेश जैसे नदियों और बारिश की भरपूर आवक वाले इलाकों में भी है। कई राज्यों में बड़ी आबादी पलायन कर गई है क्योंकि पानी के प्रबंधन के बगैर न खेती, न उद्यम, न पशु पालन, न आजीविका।

'डायनामिक ग्राउंड वॉटर रिसोर्स असेसमेंट ऑफ इंडिया' की हालिया रिपोर्ट से पता लग रहा है कि इस साल धरती ने सबसे ज्यादा पानी संजोया है। फिर भी ज्यादा राहत इसलिए नहीं होगी कि 60 फीसद से ज्यादा सिंचाई और पीने के लिए फिर निकाल लिया जाएगा। देश के जल शक्ति मंत्री चेता रहे हैं कि धरती की कोख से 166 फीसद शोषण कर रहे हैं हम। एक ओर सरकारी कोशिशें हैं, दूसरी ओर संगठनों के स्तर पर 'सुजलाम' जैसे देशव्यापी आयोजन हैं, जहां जल से जुड़ी लोक परंपराओं, शोध, देशज-ज्ञान, भारतीय-दर्शन और विज्ञान पर सार्थक संवाद हो रहे हैं।

भारत सरकार का 'हर घर जल' मिशन ज्यादातर राज्यों में अच्छी रफ्तार में है। नोबेल विजेता माइकल क्रेमर ने अपने एक शोध पत्र 'हर घर नल' से भारत में पांच साल की उम्र के सवा लाख से ज्यादा बच्चों की जान बचने का अनुमान लगाया है। साफ पानी की घर-घर पहुंच भी छोटा मसला नहीं रहा। पंजाब, गोवा, गुजरात जैसे राज्यों के हर घर को अब पानी नसीब है और बिहार जैसे राज्य भी सौ फीसदी लक्ष्य के पास हैं जबकि उत्तर प्रदेश इस मामले में अभी केवल 20 फीसद घरों तक ही पहुंच बना पाया है। राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, छत्तीसगढ़ भी नीचे के पायदानों पर ही हैं। ग्रामीण भारत में 'जल जीवन मिशन' का रिपोर्ट कार्ड मंत्रालय के डैशबोर्ड पर है। आज के दौर में आंकड़े ही आंख हैं, जिन्हें डिजिटल उंगलियां मिलने से देखने में और सहूलियत हो गई है। काम कहां धीमा है, कहां रफ्तार में, कितना लक्ष्य हासिल और कितना बाकी, सब साफ-साफ नजर आने लगा है।

जिस तरह मराठवाड़ा का इलाका किसानों की हताशा का पर्याय बन गया था, उसी तरह, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड सूखा, अभाव, पलायन, संसाधनों के शोषण और पानी के लिए झगड़ों के कारण खबरों में रहने लगा था। समाज चेता तो समाधान के लिए राजनीतिक नेतृत्व ने भी बीड़ा उठाया। बुंदेलखंड अंचल के सभी

सात जिलों-बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन और ललितपुर में छोटे बांध और तालाबों के फिर से जीवित होने के सुबूत जियो टैगिंग के जरिए मुहैया हैं। हर चेकडैम, सरोवर, तालाब की फोटो, वीडियो और सारी जानकारी पोर्टल पर है। बुंदेलखंड को मॉडल के तौर पर खड़ा करने के लिए सिंचाई-जल-कृषि विभाग, जल-शक्ति मंत्रालय और हजारों अनाम जल-सारथी जुड़े हैं। कुओं-तालाबों-खेतों को लय में लाने के लिए इस साल के आखिर तक ही विंध्याचल और बुंदेलखंड के सभी सूखे इलाकों में 'हर घर नल' पहुंच जाएगा, ऐसा दावा राज्य सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की 'अमृत-सरोवर' योजना ने 60 से ज्यादा नदियों को जीवित किया है और 58 पंचायतों के सैकड़ों सरोवरों का जीवन लौटा है।

बुंदेलखंड की महिलाओं ने 'जल-सहेली' बनकर कई गांवों को जल-समृद्ध बनने के लिए तैयार कर लिया है। पुराने जल स्रोतों को संभालने और खेती-सिंचाई में पानी की बर्बादी रोकने में वो सफल हुई हैं, तो इन्हीं पगडंडियों से चलकर पूरा इलाका मिसाल के तौर पर खड़ा दिखने को बेताब है। जल-सहेजने के अलावा जितना पानी मुहैया है, उसका प्रभावी इस्तेमाल और बूंद-बूंद की बचत से बेहतर खेती, अच्छी उपज और कमाई के लिए आधुनिक तकनीक और पारंपरिक ज्ञान दोनों के लिए बुंदेलखंड कमर कस रहा है। प्रदेश का प्रशासन, इजराइली कंपनियों के साथ 'मास्टर प्लान' भी तैयार कर रहा है, जो बाकी राज्यों के लिए भी पानी का 'रोडमैप' हो सकता है।

प्रधानमंत्री की 2017 में हुई इजराइल यात्रा के बाद हुए जल-समझौतों में बुंदेलखंड इलाका भी उन 28 जिलों में शामिल है, जहां पानी के मामले में आत्मनिर्भर होने और किसानों की आय में बढ़ोतरी के मसलों पर गहन काम होना है। इस मसले पर इजराइल सरकार के भारत में नियुक्त जल-अटैची यानी विशेषज्ञ डॉक्टर लीरोन असफ से चर्चा हुई तो उन्होंने भी बुंदेलखंड मॉडल के लिए एक नामी इजराइली कंपनी के मार्फत पानी और खेती के लिए तकनीक और समुदायों की क्षमता बढ़ाने का खाका साझा किया। इजराइली कंपनी और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच का यह करार पिछले साल ही हुआ है जिसके पहले चरण में झांसी जिले के बबीना प्रखंड के 25 गांवों में काम होगा। भारत-इजराइल-बुंदेलखंड समझौते में जल-संरक्षण, जल-कुशल और खेती की उन्नत प्रथाओं के साथ काम आगे बढ़ेगा और अगले चरण में अनुभवों से उपजी समझ से खास तौर से बुंदेलखंड इलाके के लिए जल का 'मास्टर-प्लान' भी तैयार होगा।

असल में जल और खेती की मजबूती के लिए छोटा रास्ता नहीं अपनाया जा सकता। इसके लिए जरूरी कड़ी है कि पानी के प्रबंधन और व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए सरकारी व्यवस्था पुख्ता हो। पानी का 'मास्टर प्लान' देश भर के जरूरत वाले इलाकों में लागू करने के लिए सरकारी मशीनरी की क्षमता और प्रशिक्षण, दोनों जरूरी हैं। यूं देश में जल नीति है, राज्य सरकारों की ढेरों योजनाएं हैं, और जल समस्याओं से निपटने के लिए साधन-संसाधन भी झोंके जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व की इच्छाशक्ति समाधानों को जमीन पर उतारने का बड़ा रास्ता है। जल-शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बीच के तालमेल से जो जल-मॉडल उभरेगा, वो पूरे उत्तर-प्रदेश को जल संकट से उबरने में मदद कर पाए, यह जरूरी है।

यह दौर चक्रीय अर्थव्यवस्था में हरित ऊर्जा, टिकाऊ खेती और जल-समृद्धि के साथ ही जल-परंपराओं और देशज ज्ञान को संभालने का भी है। बदलाव की इस पूरी प्रक्रिया में महिला किसानों और युवाओं के साथ साथ पूरे समाज की बेहतरी की बात भी दोहराई जानी चाहिए। समाज के बहाव में पानी से हमारा रिश्ता जितना मजबूत रहेगा, उतना ही हम जलाशयों की धरोहर के साथ-साथ, वैज्ञानिक सोच को आत्मसात कर पाएंगे। विकास के हर पक्ष को साधने का रास्ता जल-घोष से ही गुजरेगा, यह समझ जनमानस में पैरने लगी है।

यह दौर चक्रीय अर्थव्यवस्था में हरित ऊर्जा, टिकाऊ खेती और जल-समृद्धि के साथ ही जल-परंपराओं और देशज ज्ञान को संभालने का है। बदलाव की इस पूरी प्रक्रिया में महिला किसानों और युवाओं के साथ-साथ पूरे समाज की बेहतरी की बात भी दोहराई जानी चाहिए। समाज के बहाव में पानी से हमारा रिश्ता जितना मजबूत रहेगा, उतना ही हम जलाशयों की धरोहर के साथ साथ, वैज्ञानिक सोच को आत्मसात कर पाएंगे